TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 230
दि. 21.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री ने कहा- आधुनिक हवाई अड्डे और आधुनिक संपर्क अवसंरचना किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार हैं

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा - आज असम और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा-पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के भविष्य के विकास का नेतृत्व करेगा

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। असम की संपर्क व्यवस्था, आर्थिक विस्तार और वैश्विक भागीदारी में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज असम और पूर्वोत्तर के विकास और प्रगति का उत्सव है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब प्रगति का प्रकाश लोगों तक पहुंचता है, तो जीवन के हर मार्ग पर नई ऊंचाइयों को छूने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की धरती से उनका गहरा लगाव, यहां की जनता का प्यार और स्नेह तथा विशेष रूप से असम और पूर्वोत्तर की माताओं और बहनों का स्नेह तथा अपनापन उन्हें निरंतर प्रेरित करता है और इस क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि आज असम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका के शब्दों का हवाला देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इसका अर्थ है कि शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जगमगाएंगे, अंधकार की हर दीवार टूट जाएगी और यह निश्चित रूप से हो सकेगा क्योंकि यह राष्ट्र का संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा है।

श्री मोदी ने भूपेन हजारिका की पंक्तियों को केवल गीत नहीं बल्कि असम से प्रेम करने वाले हर महान व्यक्तित्व का दृढ़ संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि आज यह संकल्प पूरा हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी की प्रचंड धारा कभी नहीं रुकती, उसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में असम में विकास की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने इस नए टर्मिनल भवन के लिए असम की जनता और राष्ट्र को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले उन्हें असम के प्रथम मुख्यमंत्री और राज्य के गौरव का स्रोत गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्री बोरदोलोई ने असम की पहचान, भविष्य और हितों से कभी समझौता नहीं किया। श्री मोदी ने कहा कि श्री बोरदोलोई की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उनमें असम के लिए गहरा गौरव पैदा करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आधुनिक हवाईअड्डे और उन्नत कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा किसी भी राज्य के लिए नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोलते हैं और जनता के बीच बढ़ते विश्वास और भरोसे के स्तंभ के रूप में खड़े हैं।ह्व उन्होंने कहा कि जब लोग असम में शानदार राजमार्गों और हवाईअड्डों का निर्माण देखते हैं, तो वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि असम के लिए सही मायने में न्याय की शुरूआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने इसकी तुलना अतीत से करते हुए कहा कि पिछली सरकारों के एजेंडे में असम और पूर्वोत्तर का विकास कभी नहीं था। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों के नेता कहते थे, 'असम और पूर्वोत्तर कौन जाता है?ह्व और इस क्षेत्र में आधुनिक हवाईअड्डों, राजमार्गों और बेहतर रेलवे की आवश्यकता पर सवाल उठाते थे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इसी मानसिकता के कारण विपक्ष ने दशकों तक पूरे क्षेत्र की उपेक्षा की।

श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष द्वारा पिछले छह-सात दशकों में की गई गलतियों को उनके नेतृत्व में धीरे-धीरे सुधारा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी नेता पूर्वोत्तर का दौरा करें या न करें, असम और इस क्षेत्र में आने पर उन्हें स्वयं अपने लोगों के बीच होने का अहसास होता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनके लिए असम का विकास न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि एक जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले ग्यारह वर्षों में असम और पूर्वोत्तर के लिए लाखों-करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि असम प्रगति कर रहा है और नए मुकाम हासिल कर रहा है। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि असम भारतीय न्याय संहिता को लागू करने वाला देश का नंबर एक राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि असम ने 50 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर एक रिकॉर्ड भी बनाया है। श्री मोदी ने इसकी तुलना पिछली सरकार के दौर से की, जब रिश्वत या सिफारिश के बिना सरकारी नौकरी पाना असंभव था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज हजारों युवाओं को ऐसी प्रथाओं के बिना नौकरियां मिल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के नेतृत्व में असम की संस्कृति को हर मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने 13 अप्रैल 2023 की ऐतिहासिक घटना को याद किया, जब गुवाहाटी स्टेडियम में 11,000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ बिहू नृत्य प्रस्तुत किया था, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे नए रिकॉर्ड बनाकर असम तेजी से प्रगति कर रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि इस नए टर्मिनल भवन से गुवाहाटी और असम की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे प्रतिवर्ष 12 लाख से अधिक लोग यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इससे असम में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और श्रद्धालुओं के लिए मां कामाख्या के दर्शन करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नए हवाई अड्डे के टर्मिनल में कदम रखना विकास और विरासत के मंत्र का सही अर्थ दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हवाई अड्डे को असम की प्रकृति और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें हरियाली और व्यवस्थाएं एक इनडोर जंगल का आभास कराती हैं। उन्होंने कहा कि इसका डिजाइन चारों ओर प्रकृति से जुड़ा हुआ है ताकि प्रत्येक यात्री को शांति और आराम का अनुभव हो। उन्होंने निर्माण में बांस के विशेष उपयोग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बांस असम के जीवन का अभिन्न अंग है, जो शक्ति और सुंदरता दोनों का प्रतीक है। श्री मोदी ने यह भी याद दिलाया कि उनकी सरकार ने 2017 में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया था, जिसके अंतर्गत गैर-वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को कानूनी रूप से "वृक्ष" के बजाय "पौधे" के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने कहा कि इस कदम के परिणामस्वरूप आज एक नए टर्मिनल के रूप में एक अद्भुत संरचना का निर्माण हुआ है।

प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी में विश्वास मिलता है और स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों तक पहुंचने के रास्ते खुलते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इससे युवाओं को सबसे अधिक भरोसा मिलता है, जिनके लिए नए अवसर सृजित होते हैं।

सड़क सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी का 4-ई मॉडल, शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर पर होगा फोकस

- 108 और एएलएस एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम घटाने और स्कूल व भारी वाहनों की फिटनेस जांच के निर्देश

- वर्ष 2025 में 46 हजार से अधिक दुर्घटनाएं और 24 हजार से ज्यादा मौतें गंभीर चेतावनी

- एनएसएस, एनसीसी, आपदा मित्र, स्काउट गाइड और सिविल डिफेंस की भागीदारी होगी

- ब्लैक स्पॉट सुधार, रोड सेफ्टी ऑडिट, ओवर स्पीडिंग और लेन ड्राइविंग पर नियंत्रण के निर्देश

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेशव्यापी 'सड़क सुरक्षा माह' आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि नए वर्ष की शुरूआत केवल औपचारिक आयोजनों से नहीं, बल्कि जनजीवन से सीधे जुड़े सड़क सुरक्षा जैसे अत्यंत संवेदनशील विषय पर ठोस संकल्प, व्यापक जनभागीदारी और व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य के साथ होनी चाहिए। शनिवार को शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों, मंडलायुक्तों तथा जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा अभियान किसी भी स्थिति में औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के जीवन से जुड़ा जन आंदोलन बने।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह को 4-ई मॉडल के आधार पर संचालित किया जाए, जिसमें शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर चारों स्तंभों पर समान रूप से और समन्वित ढंग से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल नियमों की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझाना आवश्यक है कि यातायात नियमों का पालन उनके स्वयं के जीवन, उनके परिवार और समाज की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है।

वोटर लिस्ट संशोधन और घुसपैठियों पर पीएम की दो टूक, 'असम को पूर्वी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे'

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवा (19 दिसंबर 2025) को असम के गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का

उद्घाटन किया। प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस समय राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने और वोटर लिस्ट संशोधन (रक्कक) पर राजनीति तेज है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में स्पष्ट संदेश दिया है कि असम को पूर्वी पाकिस्तान बनाने की साजिश थी।

राजस्थान सीएम किसान सम्मान योजना इसी महीने जारी होगी 5वीं किस्त, फटाफट पूरे कर लें ये सारे काम

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना से जुड़े 74 लाख किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार इसी महीने योजना की 5वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, 23 तारीख को सीएम भजनलाल शर्मा किस्त जारी कर सकते हैं। जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 21वीं किस्त की राशि मिली है, वे सभी इसके लिए पात्र हैं।

इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस योजना के लिए किसानों को अलग से कोई पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद 5वीं किस्त आने से पहले कुछ जरूरी काम पूरे कर लें।

अहमदाबाद को मिली उसकी पहली 'मेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम्स प्लांट में गुजरात की सांस्कृतिक भावना को प्रतिबिंबित करने वाली अत्याधुनिक एवं आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक समान ट्रेन का स्वागत किया

यह मेट्रो ट्रेन श्रेष्ठ कोटि की फायर सेफ्टी सहित अन्य सुरक्षा सुविधाओं तथा ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 (जीओए4) के अंतर्गत पूर्णतः ऑटोमेटेड-ड्राइवरलेस ट्रेन के रूप में कार्य करने में सक्षम है

गांधीनगर,20 दिसंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद शहर को उसकी प्रथम स्वदेशी रूप से निर्मित ह्यमेक इन इंडिया' मेट्रो ट्रेन की भेंट दी।

श्री पटेल ने कोलकाता के निकट टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के आधुनिक प्लांट का दौरा कर अहमदाबाद मेट्रो रेल के कोचेस लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ह्यमेक इन इंडिया' तथा आत्मनिर्भर भारत को गति देने वाला यह महत्वपूर्ण कदम गुजरात के लिए गौरव समान है।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा उसके फैसिलिटी प्लांट में यह ट्रेन मेक इन इंडिया अंतर्गत स्वदेशी रूप से बनाई जा रही है। आधुनिक मेट्रो तथा यात्री कोच के उत्पादन के लिए सक्षम यह प्लांट अत्याधुनिक एवं आधुनिक तकनीक तथा साधन-सामग्री के साथ स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीटागढ़ प्लांट में देश के अनेक राज्यों के लोग कार्यरत हैं। यह भी एक भारत-श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री का मंत्र चरितार्थ करता है।

राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने संबोधित किया

उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में पीएससी की भूमिका को रेखांकित किया

विकसित भारत के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता निर्णायक : उपराष्ट्रपति

योग्यता केवल बरकरार ही नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि इसे बरकरार रखा जाना दिखना भी चाहिए: उपराष्ट्रपति

(जीएनएस)।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के सम्मेलन के समापन सत्र में भाग लिया और भारत की शासन प्रणाली की गुणवत्ता, ईमानदारी और प्रभावशीलता को आकार देने में लोक सेवा आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया ।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह भारत

विकसित भारत@2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है,ऐसे में शासन की गुणवत्ता, और उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण संस्थानों को चलाने वाले लोगों की गुणवत्ता निर्णायक सिद्ध होगी। उन्होंने लोक सेवा आयोगों को संवैधानिक संस्थाएँ करार दिया, जिन्हें देश की सेवा करने के लिए योग्य, निष्पक्ष और नैतिक लोगों को चुनने की अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान में प्रतिष्ठापित लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता, सरकारी भर्ती में योग्यता, निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। उन्होंने कहा कि दशकों से, केंद्र और राज्य स्तर पर आयोगों ने प्रशासनिक निरंतरता, संस्थागत स्थिरता और लोक सेवकों का तटस्थ चयन सुनिश्चित करते हुए जनता के भरोसे को मजबूत किया है।

लोक सेवाओं के संबंध में बदलती मांगों पर जोर देते हुए उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि डिजिटल शासन, सामाजिक समावेशन, अवसंरचना विकास, जलवायु कार्रवाई और आर्थिक परिवर्तन जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करना आज चुने गए प्रशासनिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह में भागीदारी की

चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण, समृद्धि और ग्रामीण विकास के प्रतीक थेह्न श्री शिवराज सिंह चौहान

'विकसित भारत-जी राम जीह्न से ग्रामीण रोजगार और विकास की नई तस्वीर बनेगी- श्री चौहान

'विकसित भारत-जी राम जीह्न में किसान और श्रमिकों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयासह्न श्री चौहान

सिर्फ मिट्टी खोदने के काम से रोजगार गारंटी की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकती थी- श्री केंद्रीय मंत्री श्री चौहान

नए कानून के जरिए स्कूल, नाली, सड़क, पुलिया यहां तक की खेत की सड़क बनाने का काम भी किया जाएगा- श्री चौहान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब कल्याण और विकास का काम करते रहेंगे- श्री शिवराज सिंह जाकर किसानों से संवाद करे रहे हैं- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में किसान ट्रस्ट द्वारा पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आयोजित चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने पुस्तक का भी विमोचन किया तथा प्रगतिशील किसान और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संस्थानों को सम्मानित किया। समारोह में शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयंत चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio FIBER
Jio Air Fiber

Jio tv+
Jio Tv +

Jio Fiber
Jio Fiber

dailyhunt
Daily Hunt

eBaba
ebaba Tv

dishtv SMART+
Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

airtel
Airtel

fire tv
Amezone Fire

Roku
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सम्पादकीय

योजनाबद्ध तरीके से विदेश विशेष कर पश्चिम को सफलता का पर्याय मानना साजिश!

आज की भारतीय युवा पीढ़ी इतिहास के निर्णायक संव्रमण काल में खड़ी है। एक ओर विदेशी जीवन की झिलमिलाती चमक, उच्च वेतन, बहुराष्ट्रीय वंपनियों की प्रतिष्ठा तथा तथाकथित ह्यग्लोबल लाइफस्टाइल' उसे लुभा रही है; दूसरी ओर स्वदेश की माटी की खुशबू, पारिवारिक प्यार, समाज का अपनापन तथा राष्ट्र–दायित्व की मौन पुकार जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान कर रही है। यह द्वंद्व केवल रोजगार या करियर का नहीं, अपितु आत्म–पहचान, सांस्वृतिक स्वाभिमान तथा राष्ट्र–भविष्य से जुड़ा गहन विमर्श है। युवाओं को निर्णय लेते समय यह ध्यान रखना होगा कि भारत अब अवसर–विहीन देश नहीं; विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है तथा ह्यविकसित भारत' के लक्ष्य हेतु संकल्पबद्ध है।आरबीआई आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्षो में लाखों युवा पेशेवर विदेश गये, कितु ह्यरिवर्स ब्रेन ड्रेन' की प्रवृत्ति भी उभर रही है। जब अपने ही देश में अवसरों का विस्तार हो रहा है, तब विदेश–आकर्षण का रहस्य क्या है? आधुनिक भारत तकनीक, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, फार्मा, वृषि–प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, हस्तशिल्प, अंतरिक्ष तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में वैश्विक वेंद्र बन रहा है। टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, टीसीएस, महिंद्रा जैसी वंपनियाँ तथा नवरत्न संस्थान बौद्धिक क्षमता, नवाचार और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बने हुए हैं। इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, एचएएल, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी तथा एम्स जैसे संस्थान अंतरिक्ष, रक्षा, चिकित्सा तथा विज्ञान में राष्ट्र–निर्माण को सशत्त कर रहे हैं।चंद्रयान–तीन की सफलता, एक साथ कई उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता, रक्षा में स्वदेशीकरण, डिजिटल इंडिया का समावेशन, 1.2 लाख स्टार्टअप्स (100ऋ् यूनिकॉर्न सहित), मेक इन इंडिया तथा नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति प्रमाणित करते हैं कि भारत अब अवसरों का निर्यातक बन चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 ने शिक्षा–शोध–नवाचार को नई दिशा दी है। नैस्कॉम रिपोर्ट्स के अनुसार, टियर–दो, तीन शहरों में लगभग चालीस प्रतिशत नई नौकरियाँ सृजित हो रही हैं तथा सरकारी योजनाएँ स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण और त्रण प्रदान कर रही हैं।फिर भी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा ऑस्ट्रेलिया आदि की ओर युवाओं का रुझान तथा माता पिता की इच्छा बनी हुई है। शायद बेहतर वेतन, जीवन–शैली तथा वैश्विक अनुभव के कारण। सोशल मीडिया, ओटीटी तथा पॉप–संस्वृति ने योजनाबद्ध तरीके से विदेश विशेष कर पमि को सफलता का पर्याय गढ़ा है।कितु भारतीय युवाओं को यह भी जानना होगा कि विदेशों में महँगाई, एकाकीपन, सांस्वृतिक दूरी, नस्लीय भेदभाव तथा मानसिक तनाव

अटल नेतृत्व, अविरत विकास : सुशासन से महिला सशक्तिकरण

■ राज्य में लखपति दीदी तथा नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाएँ बनीं आत्मनिर्भर

■ दो वर्ष में राज्य में लखपति दीदी की संख्या 5.96 लाख के पार, गाँव में रहने वालीं महिलाओं के सपने हो रहे हैं साकार

■ कंकुबेन ने कच्छी हस्तकला उत्पादों की बिक्री से वार्षिक दस लाख रुपए से अधिक की कमाई की, अब ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री

■ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर, 20 दिसंबर : सुशासन द्वारा राज्य के नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत रही है। सुदूरवर्ती नागरिकों तक विकास पहुँचाने तथा महिलाओं को सशक्त बनाकर भारत की विकास यात्रा में जोड़ने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में ह्यलखपति दीदी' योजना शुरू की गई थी। 2027 तक 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का इस योजना का उद्देश्य है। गुजरात की महिलाओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिले; इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में व्यापक प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप दिसंबर 2025 तक राज्य में लगभग 5 लाख 96 हजार महिलाओं की आय एक लाख रुपए से अधिक तक पहुँची है और वे गर्व के साथ गुजरात की ह्यलखपति दीदी' बनी हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने

कहा है, 'प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अनेक सफल आयाम अपनाए हैं। लखपति दीदी योजना के सफल क्रियान्वयन से गुजरात आगामी समय में 10 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए तैयार है।ह्व

कच्छ की कंकुबेन गर्वा की वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक

लखपति दीदी कार्यक्रम को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। कच्छ में भुज तहसील के मानकुवा गाँव में रहने वालीं कंकुबेन गर्वा का परिवार परंपरागत रूप से हस्तकला से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ह्यसरस मेला' में शामिल होकर उनके कच्छी हस्तकला उत्पाद लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। इसके बाद उन्होंने 1.5 लाख रुपए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से तथा 4 लाख रुपए के क्रेडिट कैश लोन द्वारा गाँव में ही दुकान शुरू की और स्वयं–सहायता समूह की अन्य महिलाओं को जोड़कर उत्पादन बढ़ाना शुरू किया। आज उनके उत्पाद राज्य के बाहर भी पहुँचे हैं। वे एमेजोन जैसी विख्यात ऑनलाइन साइट्स पर भी बिक्री कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही हैं। हाल में वे वार्षिक 10 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कर रही हैं और उनके कहे अनुसार उनकी इस सफलता में राज्य सरकार की ओर से लाइवलीहुड मिशन का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

नमो ड्रोन दीदी योजना से भावनाबेन को मिली नई पहचान

बनासकाँठा में काँकरेज तहसील के वरसाडा की निवासी भावनाबेन भरतकुमार चौधरी ने ड्रोन दीदी बनकर आसपास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की है और वे पशुपालन–खेती के व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव करने के प्रशिक्षण के लिए उनका चयन होने के बाद वे काँकरेज तहसील में ड्रोन दीदी के रूप में जानी जाती हैं। वे गाँव में रहकर अपने सपने साकार कर रही हैं और आसपास की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दे रही हैं। उल्लेखनीय है कि कक्षा 10 उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता के साथ 18 से 60 वर्ष आयु समूह की महिलाएँ नमो ड्रोन दीदी योजना अंतर्गत ड्रोन पायलट बन सकती हैं।

राज्य में 10 लाख से अधिक संभावित लखपति दीदी की पहचान

राज्य के प्रशिक्षित कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) द्वारा हाल में 10.74 लाख महिलाओं की पहचान की गई है, जो लखपति दीदी बन सकती हैं। चिह्नित की गईं संभावित लखपति दीदी की मौजूदा गतिविधियों तथा उनके पास उपलब्ध स्रोतों, हुए खर्च और आय का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल आजीविका रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रजिस्टर से प्राप्त जानकारी के आधार पर चिह्नित की गईं लखपति दीदी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, एसेट, आर्थिक सहायता तथा मार्केटिंग के लिए आवश्यक सपोर्ट किया जा रहा है।

कैसे काम करती है लखपति दीदी योजना ?

यह योजना स्वयं–सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायक बनती है, जिससे उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक हो सके। महिलाएँ कृषि, पशुपालन, हस्तकला तथा अन्य स्थानीय क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा बाजार से कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाती है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लखपति दीदी के लिए निम्न विवरण अनुसार आय की गणना की जाती है :

■ कृषि एवं सम्बद्ध व्यवसाय की कुल वार्षिक आय।

■ नॉन–फार्म एक्टिविटी जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज आदि की आय।

■ परिवार में कोई व्यक्ति नौकरी करता हो, तो उसकी आय।

■ फार्म तथा नॉन–फार्म व्यवसाय में मजदूरी कार्य से प्राप्त आय।

■ सरकार के योजनागत लाभ द्वारा प्राप्त राशि।

■ कमिशन, मानद् वेतन से प्राप्त आय।

248 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण

इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गुजरात सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। तहसील स्तर पर 248 मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने अब तक 10 हजार से अधिक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षण दिया है। ये कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स स्वयं–सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सहयोग देंगे। इस समग्र प्रक्रिया के लिए डिजिटल आजीविका रजिस्टर पर डेटा अपडेट किया जाता है, जो देखरेख के साथ महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग एवं मार्केट कनेक्टिविटी देने में सहायक होता है।

शुभमन गिल को वर्ल्ड कप टीम से निकालने के पीछे गौतम गंभीर और अगरकर? लखनऊ में हुई पूरी प्लानिंग

(जीएनएस)।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बीसीसीआई (इउउक) सचिव देवजीत सैकिया ने टीम का ऐलान शनिवार को किया। इस स्क्वॉड में वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को शामिल नहीं किया गया है। यह फैसला फैंस के लिए हैरान करने वाला रहा है। सोशल मीडिया पर वह ट्रेंड कर रहे हैं। अब उन्हें टीम से निकाले जाने के पीछे की कहानी सामने आई है।

बताया जा रहा है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी–20 सीरीज के दौरान ही यह फैसला हो गया था। इस बारे में किसी ने भी प्रिंस से बात नहीं की थी। शुभमन गिल को टी20 टीम से बाहर किए जाने की कोई आधिकारिक जानकारी पहले नहीं दी गई थी। उनसे इस बारे में बात भी नहीं की गई और सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

एनडीटीवी में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इउउकसे जुड़े एक सूत्र ने भी इसकी पुष्टि की है। सूत्र के मुताबिक, चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, हेड कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की शुभमन गिल को स्क्वॉड से बाहर करने के बारे में चर्चा हुई थी। यह फैसला लखनऊ में हुआ था, जहां टीम इंडिया टी–20 मैच खेलने पहुंची थी। हालांकि, प्रदूषण की वजह से मैच रद्द हो गया था। इसके बावजूद किसी ने भी शुभमन

गिल को पहले से इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें सीधे टी20 स्क्वाड से बाहर कर दिया गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूर्यकुमार यादव खुद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद उनका कप्तानी पद कम से कम टी20 वर्ल्ड कप तक सुरक्षित माना जा रहा है। मैनेजमेंट इतने अहम टूर्नामेंट से पहले कोई बड़ा बदलाव करने के पक्ष में नहीं है।

फॉर्म और फिटनेस दोनों पर संकट

– सूत्रों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान शुभमन गिल को पैर में चोट लगी थी। इस चोट ने गंभीर और अगरकर की प्लानिंग को एक और मजबूत तर्क दे दिया।

– रन बनाने के लिए उनका संघर्ष चल रहा है और उस पर लगी चोट से मामला और गंभीर हो गया। टीम मैनेजमेंट ने उनको लगी चोट के बाद विकल्पों पर विचार करने का मन बना लिया था।

– इसमें हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर की भूमिका भी बताई जा रही है।

अहमदाबाद ळ–20 मैच खेलना चाहते थे शुभमन गिल

बताया जा रहा है कि शुभमन गिल अहमदाबाद में खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में खेलना चाहते थे। हालांकि, तब तक टीम मैनेजमेंट अपना मन बना चुका था। मैनेजमेंट उन्हें टी20 स्क्वॉड से बाहर करने का फैसला ले चुका था। गिल को बिना किसी पूर्व सूचना के टीम से ड्रॉप करने के दावे ने सनसनी मचा दी है। इससे कोच और कप्तान के साथ सेलेक्टर्स के व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं। आम तौर पर फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों से टीम से निकालने से पहले बात की जाती है। राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के दौर में ऐसा किया जाता था। उससे पहले दिलीप वेंगसरकर के मुख्य चयनकर्ता रहते हुए भी यह ट्रेंड था।

बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर गिल को टीम से बाहर किए जाने को लेकर कोई ठोस वजह नहीं बता पाए थे। अब चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

दुनिया के टॉप–5 सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन से? भारत और पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी?

(जीएनएस)।

इस साल के अंत तक दुनिया में घूमने की आजादी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास किस देश का पासपोर्ट है। आज के दौर में पासपोर्ट सिर्फ पहचान का दस्तावेज नहीं, बल्कि आपकी ग्लोबल मोबिलिटी की चाबी बन चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के मुताबिक, किसी देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होता है, उसके नागरिक उतने ही ज्यादा देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यही वजह है कि हर साल इस रैंकिंग पर पूरी दुनिया की नजर रहती है।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है?

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की सबसे भरोसेमंद रैंकिंग मानी जाती है, जो यह बताती है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पहले से वीजा लिए जा सकता है। इसमें केवल वही गंतव्य गिने जाते हैं, जहां वीजा–फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। जितनी ज्यादा पहुंच, उतना ही ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है।

ïं१ एल्लीं१ 2025

सिंगापुर बना दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट

2025 में भी सिंगापुर ने अपना नंबर–1 स्थान बरकरार रखा है। सिंगापुर पासपोर्ट रखने वाले लोग दुनिया के 193 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। यह

आंकड़ा दिखाता है कि सिंगापुर की अंतरराष्ट्रीय छवि, कूटनीतिक रिश्ते और आर्थिक ताकत कितनी मजबूत है।

एशिया और यूरोप का दबदबा

दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा, जिसके नागरिक 190 देशों में वीजा–मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान ने 189 गंतव्यों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद यूरोप की एंट्री होती है। जर्मनी 188 देशों तक पहुंच के साथ चौथे स्थान पर रहा, जबकि इटली भी 188 गंतव्यों के साथ पांचवें पायदान पर मौजूद है। इससे साफ है कि एशिया और यूरोप अब भी ग्लोबल ट्रैवल फ्रीडम में सबसे आगे हैं।

भारत की रैंकिंगः सुधार की गुंजाइश बाकी

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 83वां स्थान मिला है। भारतीय पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। भले ही यह आंकड़ा बीते सालों के मुकाबले बेहतर हुआ हो, लेकिन टॉप देशों से तुलना करें तो अभी भारत को लंबा सफर तय करना है।

पाकिस्तान की स्थिति और भी कमजोर

पाकिस्तान इस सूची में 102वें स्थान पर है। पाकिस्तानी नागरिक सिर्फ 31 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पाकिस्तान की कमजोर कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय भरोसे की कमी को भी दर्शाती है।

क्यों मायने रखता है मजबूत पासपोर्ट?

मजबूत पासपोर्ट का मतलब सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस और ग्लोबल एक्सपोजर के ज्यादा मौके भी होते हैं। 2025 की यह रैंकिंग साफ दिखाती है कि आने वाले समय में देशों की सॉफ्ट पावर और अंतरराष्ट्रीय रिश्ते नागरिकों की जिंदगी पर सीधा असर डालते रहेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा संबंधी आधारभूत ढांचे में एक दशक की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पिछली शताब्दी के अंत में देश में केवल एक एम्स था, वहीं आज पूरे भारत में 23 एम्स संस्थान हैं जो हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रशिक्षण के विस्तार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं

श्री नड्डा ने केजीएमयू के स्नातकों से उत्कृष्टता बनाए रखने और चिकित्सा शिक्षा तथा शोध में योगदान देने का आग्रह किया

एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, डीएम/एम.सी.एच., एमडीएस, एमएससी, नर्सिंग और संकाय श्रेणियों में उत्कृष्ट शैक्षणिक, नैदानिक और शोध उपलब्धियों के लिए 81 छात्रों और एक संकाय सदस्य को सम्मानित किया गया

प्रविष्टि तिथिः 20 ऊए 2025 4:29ढट ु८ ढक्ष ऊॅ

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के 21 वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री ब्रजेश पाठक, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह और केन्द्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद भी उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए स्नातक छात्रों को बधाई दी और भारत में चिकित्सा विज्ञान शिक्षा और रोगी देखभाल को बढ़ावा देने में केजीएमयू के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, 'केजीएमयू को 2025 की एनआईआरएफ रैंकिंग में

8वां स्थान मिला है और इसके 12 संकाय सदस्यों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।ह्व

श्री नड्डा ने पिछले दशक में भारत के स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां पिछली शताब्दी के अंत में देश में केवल एक एम्स था वहीं आज पूरे भारत में 23 एम्स संस्थान हैं। यह हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा प्रशिक्षण का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 819 हो गई है। इसी प्रकार, स्नातक मेडिकल सीटों की संख्या 51,000 से बढ़कर 1,19,000 और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 31,000 से बढ़कर 80,000 हो गई है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निदेर्शानुसार, 2029 तक स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर 75,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिनमें से 23,000 से अधिक सीटें एक वर्ष में ही जोड़ी जा चुकी हैं।

श्री नड्डा ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आज देश में 18 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यरत हैं जो लोगों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत झ्र पीएमजेएवाई योजना के तहत भारत की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी यानी 62 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 'बुनियादी शिक्षा हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा एक विशेषाधिकार है जो समाज केवल कुछ ही लोगों को प्रदान करता है।ह्व उन्होंने यह उल्लेख किया कि सरकार प्रत्येक एमबीबीएस छात्र पर 30 से 35 लाख रुपये खर्च करती है और नए डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे अपने पेशेवर करियर की शुरूआत करते ही समाज के प्रति अधिक जिम्मेदारियां निभाएं।

श्री नड्डा ने अपने संबोधन के समापन में, स्नातक छात्रों से अकादमिक और शोध क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने और अपने पेशेवर और नैतिक आचरण में उत्कृष्टता के माध्यम से केजीएमयू की प्रतिष्ठित विरासत को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें आजीवन सीखने वाले और नवप्रवर्तक बने रहने, चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने और करुणा के साथ समाज की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

श्री ब्रजेश पाठक ने युवा डॉक्टरों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई देते हुए कहा कि केजीएमयू 120 वर्षों से अधिक समय से चिकित्सा शिक्षा, शोध और मानवता की सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा '2017 में सरकारी क्षेत्र में केवल 17 और निजी क्षेत्र में 23 मेडिकल कॉलेज थे और आज राज्य में कुल 81 पूरी तरह से कार्यरत मेडिकल कॉलेज हो गए हैं।ह्व उन्होंने आगे कहा 'आज सभी 75 जिलों में डायलिसिस और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, एनएचएम के माध्यम से 5,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं, और अतिरिक्त आईसीयू बेड के माध्यम से तृतीयक चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है।ह्व

इस अवसर पर, एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी/एमएस, डीएम/एम.सी.एच., एमडीएस, एमएससी नर्सिंग और संकाय श्रेणियों में उत्कृष्ट शैक्षणिक, नैदानिक और अनुसंधान उपलब्धियों के लिए 81 छात्रों और एक संकाय सदस्य को सम्मानित किया गया। पुरस्कारों में स्वर्ण और रजत पदक, योग्यता प्रमाण पत्र, पुस्तक पुरस्कार, नकद पुरस्कार के साथ–साथ सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध और सर्वश्रेष्ठ रेजिडेंट के लिए पुरस्कार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा और संबद्ध विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक वरिष्ठ संकाय सदस्य को विशेष सम्मान से नवाजा गया।

इस कार्यक्रम में केजीएमयू की कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद (पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित), केजीएमयू की डीन और विश्वविद्यालय विधानसभा एवं कार्यकारी परिषद की सदस्य प्रो. अपजीत कौर तथा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ईसा मसीह का कुरान में जिक्र, माना जाता है मसीहा, फिर मुस्लिम क्यों नहीं मनाते क्रिसमस? जानें

(जीएनएस)।

भर में ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भारत समेत कई देशों में यह त्योहार धार्मिक के साथ–साथ सामाजिक उत्सव का रूप भी ले चुका है। ऐसे में हर साल यह सवाल उठता है कि जब कुरान में ईसा मसीह का जिक्र कई बार आता है, उन्हें एक महान पैगंबर माना गया है, तो फिर मुस्लिम समुदाय क्रिसमस क्यों नहीं मनाता।

इस्लाम में ईसा मसीह को ईसा अलैहि सलाम कहा जाता है। कुरान में उनका नाम और उनसे जुड़ी घटनाएं लगभग 35 बार आती हैं। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ईसा मसीह अल्लाह के भेजे गए बड़े पैगंबरों में से एक हैं। उनका जन्म एक चमत्कार माना जाता है और उनकी मां मरियम को भी इस्लाम में बेहद पवित्र स्थान प्राप्त है। हालांकि, इस्लाम ईसा मसीह को पैगंबर मानता है, लेकिन उन्हें ईश्वर या ईश्वर का पुत्र नहीं मानता। यही सबसे बड़ा धार्मिक अंतर है।

इस्लाम में ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह के भेजे गए महान पैगंबरों में शामिल किया जाता है। कुरान उन्हें पैगंबर मोहम्मद से पहले आने वाले एक अहम संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करता है।

दिलचस्प बात यह है कि कुरान में ईसा का जिक्र पैगंबर मोहम्मद से भी ज्यादा बार हुआ है। कुरान में कम से कम 35 बार उनका जिक्र मिलता है, जिनमें 27 बार ईसा या यीशु के नाम से और 8 बार "मसीहा" के रूप में उनका उल्लेख किया गया है।

मुसलमान और ईसाई, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि ईसा का जन्म असाधारण था। इस्लामी मान्यता के मुताबिक मरियम ने अल्लाह के हुक्म से बिना पिता के ईसा को जन्म दिया। इसे उसी तरह का चमत्कार माना जाता है, जैसे आदम को बिना माता–पिता के पैदा किया गया था। इस्लाम के मुताबिक ईसा ने लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का संदेश दिया, ठीक वैसे ही जैसे उनसे पहले और बाद में आने वाले सभी पैगंबरों ने किया।

हालांकि, ईसा के अंत को लेकर दोनों धर्मों की मान्यताएं अलग हैं। ईसाई मानते हैं कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जबकि इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने ईसा को बचा लिया था और उन्हें स्वर्ग बुला लिया। मुसलमान यह भी मानते हैं कि कयामत से पहले ईसा मसीह दोबारा धरती पर लौटेंगे। यही विश्वास ईसाई धर्म में भी मिलता है, जहां उनकी वापसी को दुनिया के अंत से जुड़ा एक बड़ा संकेत माना जाता है।

क्रिसमस ईसाई धर्म में ईसा मसीह के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ईसाई मान्यता के मुताबिक ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और इसी विश्वास के साथ यह पर्व जुड़ा हुआ है। इस्लाम में इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जाता। इस्लाम की बुनियाद इस विश्वास पर टिकी है कि अल्लाह ने इंसानियत की हिदायत के लिए कई पैगंबर भेजे और सभी पर ईमान लाना जरूरी है। इसी वजह से मुसलमान ईसा अलैहि सलाम को भी दिल से मानते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। इसके बावजूद मुसलमान क्रिसमस नहीं मनाते, क्योंकि इस त्योहार से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं इस्लाम की शिक्षाओं से मेल नहीं खातीं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

भोपाल में आज उत्तर-मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक आयोजित हुई

भारत विकसित@2047 तब होगा जब हर घर, गांव, शहर और राज्य विकसित और आत्मनिर्भर होगाः श्री मनोहर लाल

(जीएनएस)।

माननीय केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शहरी विकास मंत्रियों की तीसरी क्षेत्रीय बैठक 20 दिसंबर, 2025 को भोपाल में आयोजित की गई।

नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2025 को शहरी विकास मंत्रियों की राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित हुई जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर इस परामर्श की नींव रखी गई। बेंगलुरु में 30 अक्टूबर, 2025 और हैदराबाद में 18 नवंबर, 2025 को आयोजित पहली और दूसरी क्षेत्रीय बैठकों के अनुरूप, विचार-विमर्श, शहरी विकास के प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित थे ताकि सामूहिक रूप से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

इस बैठक में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के माननीय शहरी विकास एवं आवास विभाग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश की माननीय शहरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा बागड़ी, छत्तीसगढ़ के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शहरी प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साओ, राजस्थान के माननीय शहरी विकास एवं स्थानीय स्वशासन विकास राज्य मंत्री श्री झबर सिंह खर्रा, उत्तर प्रदेश के माननीय शहरी विकास, शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन एवं ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश के माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर और

संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग के सहयोग से इस क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उत्तर मध्य राज्यों, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सहित शहरी विकास मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एक साथ आए।

अपने आरंभिक भाषण में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा, जब हर घर, गांव, शहर और राज्य विकसित और आत्मनिर्भर होगा। माननीय केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 टूलकिट जारी किया। सरल, सुविधाजनक और प्रभावी नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सात आईटी प्लेटफॉर्म के वीडियो का शुभारंभ भी किया।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न केंद्रीय मिशनों की प्रगति की समीक्षा की।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी ने डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) के ढांचे के अंतर्गत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व द्वारा डंपसाइटों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया जिसमें सुधार प्रयासों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी भागीदार राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वे मेंटर और मेंटी शहरों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से स्वच्छ शहर जोड़ी (एसएसजे) के तहत तैयार की गई कार्य योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन करें।

अटल पुनर्जीवन एवं शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) के अंतर्गत, माननीय मंत्री जी ने जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने, शहरी जल एवं स्वच्छता संसाधनों की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करने तथा उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को अधिकतम करने की आवश्यकता पर बल दिया। सभी भागीदार राज्यों से परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने, समन्वय बढ़ाने और नल जल आपूर्ति एवं सीवरेज कवरेज में संतृप्ति प्राप्त करने का आग्रह किया गया।

'सभी के लिए आवास' अभियान के अंतर्गत माननीय केंद्रीय मंत्री ने निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के घरों के निर्माण को पूरा करने और पीएमएवाई-2.0 के घरों की नींव रखने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को एएचपी (सभी के लिए आवास) घरों में अधिभोग सुनिश्चित करने और लाभार्थियों को गृह ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस उद्देश्य के लिए, अंगीकार अभियान मार्च 2026 तक जारी रहेगा और पीएमएवाई लाभार्थियों को विभिन्न लाभों का एकीकरण करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा।

पीएम-ईबस सेवा योजना से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ मेट्रो नेटवर्क के सघनीकरण और शहरी परिवहन के अंतर्गत फर्स्ट-लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर चर्चा की गई।

राज्य मंत्रियों ने क्षेत्रीय परामर्शों के माध्यम से राज्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से जुड़ने के लिए गृह मंत्रालय (एमओएचयूए) के दृष्टिकोण की सराहना की। भारत के शहरी परिवर्तन की यात्रा को गति देने के लिए साझा प्राथमिकताओं, क्षेत्रीय अवसरों की पहचान करने और सहकर्मी सीखने के लिए सुधार के रास्ते तय करने के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाएंगी।

माननीय केंद्रीय मंत्री ने नई मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की।

चौथी मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक, 23 लाख से ज्यादा अभिभावकों की भागीदारी

(जीएनएस)।

पंजाब की भगवंत मान सरकार की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में अहम सुधार के काम चल रहे हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मेगा अभिभावक-शिक्षक बैठक शनिवार (20 दिसंबर) को आयोजित की गई थी। यह चौथी पैरंट-टीचर मीटिंग है, जिसमें 23.30 लाख से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालिकाएं), श्री आनंदपुर साहिब में पीटीएम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं 'आप' पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने जिला होशियारपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पददी सूरा सिंह में मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया।

विधायकों और अधिकारियों ने 7500 से अधिक स्कूलों का दौरा किया

इस बैठक के संबंध में विधायकों, स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा, एस.सी.ई.आर.टी. की निदेशक किरण शर्मा, उपायुक्तों और शिक्षा विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने 7500 से अधिक स्कूलों का दौरा किया। शिक्षा मंत्री बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंजाब सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से 'मां-पिता की भागीदारी' (अभिभावकों की साझेदारी) की थीम के तहत अभिभावकों और स्कूलों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े स्तर की पहल अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाकर विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों को

बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दिखाती है।

मेगा कार्यशाला के लिए 40,000 शिक्षकों को दी गई ट्रेनिंग

शिक्षा मंत्री ने बताया कि अभिभावक कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। 40,000 से अधिक शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई। हरेक सरकारी स्कूल से कम से कम एक शिक्षक को इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत जहां प्रशिक्षित शिक्षक संवाद सत्रों का संचालन करते हैं, वहीं एसएमसी सदस्य अभिभावकों के साथ समन्वय और अन्य सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता हेतु अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।

प्री-प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के बच्चों के अभिभावकों ने लिया हिस्सा

उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1-1.5 घंटे की अभिभावक कार्यशाला के बाद मेगा पीटीएम को साझा कार्यशाला डिजाइन और एसएमसी-नेतृत्व वाली बैठक योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाता है। अभिभावकों को जानकारी के लिए हैंडआउट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका को सुदृढ़ करना, घर और स्कूल में सक्रिय व सकारात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, समग्र बाल विकास के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के बीच मजबूत सहयोग सुनिश्चित करना है।

पंजाब की अअढ सरकार ने शहीदी सभा के लिए फतेहगढ़ साहिब में करवाए ये खास इंतजाम, उट भगवंत मान ने दी हर डिटेल

उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जिम्मेदारियों की साझा समझ विकसित करते हुए अभिभावकों और स्कूलों के बीच मजबूत आपसी संबंध सुनिश्चित करती है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है। यह पहल घर और स्कूल के बीच तालमेल को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, नियमित उपस्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक-शिक्षक बैठक के दौरान संवाद विद्यार्थियों के प्रयासों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना से शुरू होता है। इससे बातचीत के लिए सकारात्मक और सम्मानजनक आधार सुनिश्चित होता है। इस प्रक्रिया से बच्चों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, क्योंकि संवाद के दौरान शिक्षक और अभिभावक विद्यार्थियों की रुचियों, आकांक्षाओं और शैक्षणिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हैं तथा एक-दूसरे से फीडबैक लेते हैं।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह की एक नई पहल है, जिसके माध्यम से अभिभावकों को शैक्षणिक लक्ष्यों और शिक्षा क्षेत्र में आगामी पहलों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि वे घर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल मेट्रो का उद्घाटन किया

भोपाल भारत का 26वां शहर बन गया जहां मेट्रो नेटवर्क संचालित हो रहा है;

भारत की कुल संचालित मेट्रो लंबाई 1,090 किमी पहुंच गई

प्रविष्टि तिथिः 20 ऊएउ 2025 7:06ढट_८ ढक्ह ऊै

भोपाल में मेट्रो सेवाओं की शुरूआत के साथ भारत की शहरी परिवहन यात्रा में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। भोपाल के शामिल होने के साथ, देश भर में 26 शहरों में मेट्रो सेवाएं अब संचालित हो रही हैं, जिससे भारत में कुल संचालित मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 1,090 किमी हो गई है।

भोपाल मेट्रो मध्य प्रदेश की राजधानी शहर के लिए एक बड़ा कदम है, जो नागरिकों के लिए शहरी यात्रा को तेज, स्वच्छ और अधिक सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित यह परियोजना स्मार्ट, हरित और टिकाऊ गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है।

भोपाल मेट्रो की कुल लंबाई 30.8 किमी है, जिसमें दो कॉरिडोर और एक डिपो शामिल हैं:

ऑरेंज लाइनः 16.74 किमी

ब्लू लाइनः 14.16 किमी

शहर के प्रमुख व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए डिजाइन की गई यह मेट्रो ट्रैफिक जाम को कम करने और निवासियों के समग्र जीवन स्तर को इससे बेहतर बनाने की उम्मीद है।

प्राथमिकता कॉरिडोर का उद्घाटन

भोपाल मेट्रो के पहले चरण, ऑरेंज लाइन प्राथमिकता कॉरिडोर का आज उद्घाटन किया गया। लगभग 7 किमी लंबे इस प्राथमिकता खंड में आठ ऊंचे स्टेशन शामिल हैं: AIIMS, अलकापुरी, DRM ऑफिस, रानी कमलापति, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा, केंद्रीय विद्यालय और सुभाष नगर।

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने अमरावती में वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय में आंध्र प्रदेश के पहले जेनरेशन-जेड परिवर्तित परिसर डाकघर का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने कैंपस डाकघरों के आधुनिकीकरण और उन्हें छात्र-केंद्रित सेवा केंद्रों में बदलने की राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत, जेनरेशन-जेड विषय पर आधारित वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय उप डाकघर का अमरावती स्थित वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय परिसर में आज उद्घाटन किया।

उद्घाटन समारोह में आंध्र प्रदेश सर्कल की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल सुश्री बीपी श्रीदेवी, आईपीओएस; वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पी. अरुलमोलीवरमन; गुंटूर जिले की कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती ए. थमीम अनासरिया, आईएएस; वीआईटी-एपी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. जगदीश चंद्र मुदिगंती; विजयवाड़ा क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल डॉ. वेन्नम उपेंद्र, आईपीओएस; आंध्र प्रदेश सर्कल के महाप्रबंधक (वित्त) श्री के. विनोद कुमार, आईपी एंड टीएएफएस;

और लेखा निदेशक श्री अभिलाष पासम, सहित कई गणमान्य व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी और संकाय सदस्य उपस्थित थे।

यह पहल भारत डाक अभियान के एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है जो युवा भारत से जुड़ती है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती और कैंपस परिवेश के भीतर आधुनिक, सुलभ सेवाएं प्रदान करती है।

यह पहल इंडिया पोस्ट के परिवर्तन के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक डाकघरों को समकालीन, भविष्य के लिए तैयार संस्थानों के रूप में पुनर्परिभाषित करना और युवा पीढ़ी के साथ जुड़ाव को मजबूत करना है। नए सिरे से तैयार किए गए डाकघर को सोच-समझकर जेनरेशन-जेड की सोच के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जिसमें कार्यक्षमता, रचनात्मकता, नवाचार और आधुनिक सौंदर्यशास्त्र का संयोजन है।

जेनरेशन-जेड विशेष पर आधारित इस डाकघर में नई पीढ़ी की सुविधाएं जैसे दीवारों पर भारतीय डाक से जुड़े साहित्य का प्रदर्शन , कॉफी की सुविधा, फुटबॉल टेबल, मुफ्त वाई-फाई, पत्रिकाएं और उन्नत डिजिटल सेवा उपलब्ध हैं, जो इसे एक स्वागत योग्य और छात्र-अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने "वीआईटीः आंध्र प्रदेश का जेनरेशन-जेड थीम वाला डाकघर" शीर्षक से एक विशेष डाक कवर भी जारी किया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने कहा कि यह पहल डाक विभाग की डाकघरों को युवा नागरिकों की बदलती आकांक्षाओं के अनुरूप जीवंत सेवा केंद्रों में बदलने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी पहल छात्रों को आवश्यक डाक, वित्तीय और डिजिटल सेवाओं से सुलभ और रुचिकर तरीके से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

विशेष रूप से जेनरेशन-जेड उपयोगकर्ताओं के लिए परिकल्पित, कैंपस डाकघर सरलीकृत सेवा वितरण, डिजिटल भुगतान विकल्प और डाक, बैंकिंग और बीमा सेवाओं तक एक ही छत के नीचे निर्बाध पहुंच प्रदान करता है। यह पहल नवाचार, समावेशिता और ग्राहक-केंद्रित सेवा वितरण पर भारतीय डाक के लक्ष्य को सुदृढ़ करती है और छात्रों के बीच वित्तीय जागरूकता को बढ़ावा देती है।

कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद इस दिन बिहार आ रहे हैं नितिन नबीन

(जीएनएस)।

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आगामी 23 दिसंबर को पहली बार पटना आ रहे हैं। उनके इस पहले बिहार आगमन को लेकर प्रदेश भाजपा में भारी उत्साह है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि बांकीपुर के विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन का स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं होगा।

पूरे पटना को सजाया जा रहा है और कार्यकताओं के साथ-साथ आम जनता भी उनके अभिनंदन के लिए तैयार है। यह दौरा बिहार भाजपा के लिए संगठन और सरकार के बीच नए समन्वय की शुरूआत माना जा रहा है।

जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू

नितिन नवीन के पटना आगमन को लेकर भाजपा कार्यकताओं ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के अनुसार, 23 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे उनके हवाई अड्डे पर उतरते ही भव्य स्वागत किया जाएगा। पटना की सड़कों को होर्डिंग्स और

झंडों से पाट दिया गया है। बांकीपुर से विधायक होने के नाते स्थानीय जनता में भी अपने नेता के राष्ट्रीय कद बढ़ने को लेकर जबरदस्त गौरव का भाव है, जिसे यादगार बनाने के लिए पूरा शहर सज-धज कर तैयार है।

पंचमुखी हनुमान मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

नितिन नवीन का रोड शो पटना हवाई अड्डे से शुरू होकर शेखपुरा और राजवंशी नगर पहुंचेगा, जहां वे पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद उनका काफिला पुनाईचक होते हुए हाई कोर्ट पहुंचेगा। वहां वे संविधान निमार्ता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके उपरांत, वे आयकर गोलंबर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण (खढ) की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इन प्रतीकात्मक कार्यों के जरिए भाजपा अपने वैचारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संदेश जनता तक पहुंचाना चाहती है।

मिलर हाई स्कूल में ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह

नितिन नवीन के स्वागत समारोह का मुख्य केंद्र ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल का मैदान होगा। यहां बिहार भाजपा की ओर से एक विशाल अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें राज्य भर से हजारों कार्यकताओं के जुटने की संभावना है। इस समारोह के माध्यम से भाजपा अपनी सांगठनिक एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन कार्यकताओं को संबोधित करेंगे, जिससे आगामी चुनावों और संगठन विस्तार को लेकर नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।

मोटापे का इलाज शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता; भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाएं, वजन घटाने वाली दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करेंः डॉ. जितेंद्र सिंह

मंत्री महोदय ने दो दिवसीय "एशिया ओशिनिया कॉन्फ्रेंस ऑन ऑबेसिटी" (एओसीओ) के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, इसमें डॉ. क्यौंग कोन किम, डॉ. वोल्कान युमुक, डॉ. महेंद्र नरवारिया और अन्य सहित इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया;

मंत्री महोदय ने कहा कि मोटापा एक गंभीर समस्या है जिसे केवल डॉक्टर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता; हर नागरिक की इसमें भूमिका है

भारत में 63% मौतें गैर-संक्रामक रोगों से जुड़ी हैं जो किसी न किसी रूप में मोटापे से संबंधित हैं; अब समाज में जागरूकता का समय आ गया है- डॉ. जितेंद्र सिंह

फिट इंडिया, खेलो इंडिया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आहार पर ध्यान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता को दशार्ता है

(जीएनएस)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि वर्तमान में उपलब्ध वजन घटाने वाली या मोटापा कम करने वाली दवाओं का उपयोग बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

मंत्री जी, जो स्वयं एक प्रख्यात मधुमेह विशेषज्ञ और चिकित्सा के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि मोटापा एक जटिल, दीर्घकालिक और बार-

बार होने वाला विकार है, न कि केवल एक सौंदर्य संबंधी या जीवनशैली से जुड़ी चिंता। उन्होंने भारत की सबसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक के रूप में उभरी इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समग्र समाज के दृष्टिकोण का आह्वान किया।

डॉ. क्यौंग कोन किम, डॉ. वोल्कान युमुक, डॉ. महेंद्र नरवारिया, डॉ. बीएम मक्कर, डॉ. बंशी साबू और अन्य सहित क्षेत्र के कुछ प्रमुख विशेषज्ञों की उपस्थिति में आयोजित दो दिवसीय "एशिया ओशिनिया कॉन्फ्रेंस ऑन ऑबेसिटी" (एओसीओ) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों, शोधकर्ताओं, नीति निमार्ताओं और अन्य हितधारकों का एक मंच पर एकत्रित होना ही भारत में मोटापे की महामारी की बढ़ती गंभीरता को दशार्ता है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल एक अर्थशास्त्री के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, उसी प्रकार मोटापा भी इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल एक चिकित्सक या महामारी विज्ञानी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इसकी गहरी सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जड़ें हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में गैर-संक्रामक रोगों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है जो किसी न किसी रूप में मोटापे से जुड़े हैं और इनका कुल मृत्यु दर में लगभग 63 प्रतिशत का योगदान है। उन्होंने बताया कि टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी स्थितियां मोटापे से जुड़ी हैं, जिनमें केंद्रीय या आंतरिक मोटापा भी शामिल है, जो विशेष रूप से भारतीयों में प्रचलित है और शरीर के कुल वजन से परे भी स्वतंत्र स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि भारतीय संदर्भ में किसी प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय मंचों से बार-बार मोटापे और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बारे में बोलना अभूतपूर्व है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खान-पान की आदतों और दैनिक दिनचर्या में छोटे, निरंतर बदलावों पर प्रधानमंत्री का बल मोटापे को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देता है। यह फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसी पहलों और निवारक स्वास्थ्य देखभाल के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 से स्वास्थ्य राष्ट्रीय नीति निर्माण के केंद्र में आ गया है और सरकार रोकथाम, किफायती और शीघ्र जांच पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत, व्यापक जांच कार्यक्रमों और स्वदेशी टीकों के विकास सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को इस बदलाव के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आयुष मंत्रालय के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को एकीकृत करने पर सरकार के जोर का भी उल्‍लेख किया।

मंत्री जी ने मोटापे की रोकथाम से जुड़े बढ़ते व्यवसायीकरण और भ्रामक सूचनाओं के प्रति आगाह किया और चेतावनी दी कि अवैज्ञानिक दावे और तथाकथित त्वरित समाधान अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं और उन्हें प्रमाण-आधारित देखभाल से दूर करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल औपचारिक अनुमोदन ही नैदानिक अभ्यास में पूरी सच्चाई नहीं बताते, और याद दिलाया कि कैसे पूर्व के दशकों में रिफाइंड तेलों के व्यापक उपयोग से अनपेक्षित दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम सामने आए। जनहित की रक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने मिथकों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से आधुनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के जिम्मेदार उपयोग के माध्यम से निरंतर प्रयासों का आह्वान किया।

युवा पीढ़ी तक पहुंचने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जन जागरूकता को चिकित्सा सम्मेलनों और विशेषज्ञ चचाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें न केवल जानकार लोगों से बात करनी चाहिए, बल्कि उन लोगों से भी बात करनी चाहिए जो यह नहीं जानते कि वे नहीं जानते।" उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत के युवाओं के स्वास्थ्य और ऊर्जा की रक्षा करना आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने किया पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभः 5 साल तक के बच्चों को लगेगा टीका

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की शुरूआत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने शनिवार को औपचारिक रूप से की। उन्होंने जिला अस्पताल परिसर में पहले बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का लक्ष्य 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो का टीका लगाना है, ताकि जिले को पोलियो मुक्त रखा जा सके।

डीएम ने बताया कि अभियान दो दिवसीय है, जो 20 और 21 दिसंबर को चलेगा। पहले दिन सुबह 7 से शाम 5 बजे तक बूथों पर टीकाकरण होगा, जबकि दूसरे दिन छूटे हुए बच्चों को कवर किया जाएगा। जिले में 1500 से अधिक बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां आशा कार्यकर्ता, एएनएम और वॉलंटियर्स तैनात हैं। कुल 2.5 लाख बच्चों को लक्ष्य बनाया गया है।

सीएमओ डॉ. एके सिंह ने कहा कि अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है, और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा। जिलाधिकारी ने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नजदीकी बूथ पर लाकर टीका लगवाएं। अभियान की सफलता के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मैदान में उतरेंगे।

पीलीभीत :-अखिल भारत हिन्दू महासभा बीसलपुर की मासिक बैठक सम्पन्न, संगठन विस्तार पर हुआ मंथन

(जीएनएस)।

बीसलपुर।

अखिल भारत हिन्दू महासभा बीसलपुर नगर इकाई द्वारा शनिवार, दिनांक 20 दिसंबर 2025 को एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य संगठन को सशक्त बनाना, हिन्दू समाज को सनातन धर्म के प्रति जागरूक करना तथा वर्तमान सामाजिक व राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार-विमर्श करना रहा।

बैठक की अध्यक्षता नगर संरक्षक नरेश चंद्र शर्मा कातिब ने की, जबकि बैठक का सफल संचालन नगर महामंत्री महन्त अवनीश रतन द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत हिन्दू समाज की एकता और सनातन मूल्यों को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश में आए दिन हो रही लव जिहाद जैसी घटनाएं हिन्दू समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार से सख्त कानून बनाए जाने की मांग की गई। साथ ही देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बिल को शीघ्र पारित करने, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने तथा भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

नगर महामंत्री महन्त अवनीश रतन ने अपने संबोधन में कहा कि हिन्दू समाज पर यदि किसी भी प्रकार का अन्याय या समस्या आती है, तो अखिल भारत हिन्दू महासभा सदैव उनके साथ खड़ी है। संगठन समाज के प्रत्येक पीड़ित हिन्दू की आवाज बनेगा और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगा।

बैठक में हिन्दू महासभा पश्चिमी प्रान्त प्रभारी विवेक श्रीवास्तव, महिला मंडल नगर अध्यक्ष बबिता सक्सेना, नगर अध्यक्ष सुनील अवस्थी, युवा नगर अध्यक्ष दीपक मौर्य, नगर मंत्री महन्त मुकेश गोस्वामी, नगर उपाध्यक्ष अनूप कुमार, युवा नगर महामंत्री प्रतीक सक्सेना, नगर मंत्री रवि यादव, शिवम गंगवार, सुखपाल मौर्य, बाबा रामप्रिय दास सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान संगठन विस्तार की दिशा में नगर टीम का गठन भी किया गया। इसमें सुखपाल मौर्य को युवा नगर मंत्री, कृष्णा वर्मा को युवा नगर उपाध्यक्ष तथा बब्लू को नगर युवा कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। इसके साथ ही महिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें कृति शर्मा को नगर अध्यक्ष तथा नैना देवी को नगर महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक का समापन संगठन की मजबूती, हिन्दू समाज की एकता और राष्ट्रहित में कार्य करने के संकल्प के साथ किया गया।

अनियंत्रित ट्रक ने तोड़ी घर की दीवार,गर्भवती महिला गंभीर घायल; सरकारी राशन लादे ट्रक का हादसा, जिला अस्पताल रेफर

(जीएनएस)।

पीलीभीत,थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के बासूपुर गांव में शनिवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे मकान की दीवार तोड़ दी। हादसे में घर के अंदर बर्तन धो रही गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ट्रक सरकारी राशन से लदा था, जिसे रायपुर विचपुरी ले जाया जा रहा था। घायल महिला को पूरनपुर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना सुबह करीब 8 बजे घटी। गांव निवासी फजलुर रहमान के मुख्य सड़क से सटे मकान पर ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार ट्रक ने सीधे दीवार से टक्कर ली, जो धसक गई। चपेट में आने से मेहनिमा पत्नी फिरदौस (25 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें तुरंत पूरनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया, लेकिन डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उनका इलाज जारी है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। चालक ने बताया कि ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। ग्रामीणों ने शिकायत की कि इलाके में ओवरलोड ट्रकों का आवागमन आम है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक कार्रवाई न होने से नाराजगी है। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर सख्ती व सड़क सुरक्षा उपायों की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी: मिशन शक्ति टीम ने दो युवकों को पकड़ा, मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पूरनपुर क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत दो युवकों को छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटना से इलाके में सतर्कता बढ़ गई है।

मिशन शक्ति टीम के एसआई नरेंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार को टीम कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों की जांच के दौरान एपी इंटर कॉलेज के बाहर पहुंची। वहां मोहल्ला गणेशगंज पूर्वी के निवासी सोहेल (22) और समद (20) छात्राओं पर अश्लील टिप्पणियां कर रहे थे। टीम ने तुरंत दोनों को हिरासत में लिया और पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज किए।

एसआई ने प्राथमिकी में उल्लेख किया कि आरोपी युवक कॉलेज के निकट घूमते हुए अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जिससे छात्राओं में डर का माहौल बन गया। पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। एसपी ने मामले को गंभीर बताते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मिशन शक्ति टीम ने अभिभावकों व छात्राओं से सतर्क रहने की अपील की

विवाहिता ने पति सहित 6 लोगो के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। ससुराली जनो की प्रताड़ना से परेशान विवाहिता ने पति सहित 6 लोगो के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।

मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम बनियातारा निवासी हरिश्चंद्र वर्मा की पुत्री रुमा की एक वर्ष पूर्व थाना क्षेत्र के ग्राम गह्वरैला निवासी जग्गनाथ वर्मा के पुत्र विकास वर्मा के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी शादी मे विदाई के बाद से विवाहिता के पति विकास वर्मा, ससुर जग्गन्नाथ, सास दुलारी, जेठ आकाश वर्मा व जेठानी शिल्पा दहेज मे कार व सोने की जंजीर को लेकर प्रताड़ित करते रहे जिसकी शिकायत कई बार अपने पिता से की लेकिन पिता ने हर बार समझा बुझा कर ससुराल भेज देते थे लेकिन ससुराली जन आये दिन परेशान करते रहे जिससे तंग पीड़िता ने सुसराली जनो के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है ।

लाइसेंसी रिवॉल्वर से चली गोली, युवक की मौत; पूर्व उक्सऋकर्मी की पत्नी घायल, पैसों के विवाद में हादसा

(जीएनएस)।

पीलीभीत,पूरनपुर क्षेत्र के नारायणपुर ग्राम पंचायत में सेवानिवृत्त सीआईएसएफ कर्मी के घर पैसों के लेनदेन पर विवाद के दौरान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई। घटना में मेजबान की पत्नी भी घायल हुई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

घटना शनिवार सुबह बंडा रोड पर पूर्व सीआईएसएफ कर्मी पूरन सिंह के आवास पर घटी। थाना मझोला के टोडरपुर गांव निवासी सुखदेव सिंह (30) पूरन सिंह के घर आया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर बहस हुई। इसी दौरान पूरन सिंह की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चल गई, जो सुखदेव सिंह को लगी। सुखदेव की मौके पर मौत हो गई, जबकि पूरन सिंह की पत्नी गुरमीत कौर को भी गोली चली, जिससे वे घायल हो गईं।

सूचना पर सीओ प्रतीक दहिया व कोतवाल पवन कुमार पांडे पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया, साक्ष्य एकत्र किए। गुरमीत कौर को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जबकि सुखदेव के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाल ने बताया कि जांच में घर के अन्य सदस्यों से पूछताछ हो रही है, ताकि गोली चलने की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट हों। प्रथम दृष्टया यह हादसा लग रहा, लेकिन सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही। परिवार ने सहयोग का भरोसा दिया।

लगाई गई कंटीली तार में एक नीलगाय फंसकर गंभीर रूप से घायल

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। खेत की फसल को बचाने के लिए किसानो द्वारा खेत के चारो तरफ ललगाई गई कंटीली बाड़ में एक नीलगाय फंसकर गंभीर रूप से घायल गाई गई कंटीली बाड़ में एक नीलगाय फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे गोसेवको ने नीलगाय के प्राण बचाते हुए पशु चिकित्सालय के पैरावेट की मदद से इलाज कराया। ग्रामीणों के अनुसार कंटीली बाड़ में फंसी नीलगाय जितना निकलने का प्रयास करती उतना ही घायल होती जाती।

शनिवार की भोर शौच के लिए गये अमदहा के ग्रामीणों ने देखा कि एक नीलगाय कंटीले तारों के बींच फंसी हुई है जिसकी जानकारी जब गांव के गोसेवकों को हुई तो गोसेवकों की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई और वन दरोगा गिरजेश कुमार सिंह को सूचना दी। सूचना पर पहुँचे वन दरोगा श्याम लाल ने पशु चिकित्सालय मसौली के पैरावेट राजू यादव एव गौसेवक उमाकांत ,विशाल की मदद से

रेस्क्यू कर नीलगाय को किसी तरह से तारों से निकाल कर नीलगाय का इलाज किया। इस मौके पर वन कर्मी गिरजेश कुमार सिंह, दैनिक वाचर शिवराम,एखलाक हुसैन सहित गांव के अन्य लोग मौजूद रहे।

पीलीभीतः गन्ना किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु टोल-फ्री नंबर व व्हाट्सएप सुविधा–जिला गन्ना अधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

(जीएनएस)।

पीलीभीत। गन्ना विकास विभाग ने किसानों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। सूचना विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, किसान टोल-फ्री नंबर 18001213203 पर कॉल कर या व्हाट्सएप 7081202121 पर समस्या दर्ज करा सकते हैं। गन्ना सर्वे, जमीन दर्ज कराने व अन्य मुद्दों के लिए सर्किल गन्ना पर्यवेक्षक या ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के सीयूजी नंबर पर संपर्क करें।

ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के नंबरः पीलीभीत (7081202507), बरखेड़ा (7081202511), मझोला (7081202510), बीसलपुर (7081202509), पूरनपुर (7081202508)। आधार, मोबाइल, बैंक खाता दर्ज कराने व गन्ना कैलेंडर के लिए सहकारी गन्ना विकास समिति बीसलपुर-पूरनपुर (7081202327), पीलीभीत-मझोला (7081202337); मुख्य गन्ना अधिकारी बीसलपुर (7880888964), पूरनपुर (7880888969)।

जिला गन्ना अधिकारी ने सभी निरीक्षकों व पर्यवेक्षकों को सीयूजी पर कॉल विवरण रखने व समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। यदि कोई नंबर बंद मिले या कर्मचारी अनसुना करे, तो जिला गन्ना अधिकारी के नंबर 7081202230 पर शिकायत करें। चीनी मिलों, गन्ना विकास परिषदों व समितियों पर हेल्प डेस्क स्थापित हैं। ज्येष्ठ निरीक्षक व सचिव सुबह 10 से 12 बजे कार्यालय में अनिवार्य उपस्थित रहेंगे। उल्लंघन पर कठोर विभागीय कार्रवाई होगी।

किसानों से अपीलः त्वरित समाधान के लिए इन नंबरों का उपयोग करें। (किसान हित!

पीलीभीतः मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज सहायता के आवेदन कम–अपर जिलाधिकारी ने जागरूकता व आवेदन प्रक्रिया पर जोर दिया

(जीएनएस)।

पीलीभीतअपर जिलाधिकारी (वि./रा.) प्रसून द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत निर्धन व असहायक व्यक्तियों को इलाज आदि के लिए आर्थिक सहायता के आवेदन बहुत कम आ रहे हैं। इससे योजना के प्रति जनता में जागरूकता की कमी झलकती है। सूचना विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रों को तुरंत आवेदन करना चाहिए।

प्रसून द्विवेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई व क्षेत्र भ्रमण के दौरान पात्र व्यक्तियों से आवेदन, पंजीकृत/राजकीय चिकित्सालय का आगणन (इलाज व्यय का अनुमान), आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में भेजें। वैकल्पिक रूप से, जन सुनवाई पोर्टल पर ऑपरेटर आईडी से ऑनलाइन आवेदन कराएं।

इससे जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन ने अपील की कि पात्र व्यक्ति आगे आएं व योजना का लाभ उठाएं। (सहायता का अधिकार!)

स्वनिधिः रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं का सशक्तिकरण

(जीएनएस)।

प्रमुख बिन्दु

पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्ष्य 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को लाभान्वित करने का है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

ऋण वितरण अवधि को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाया गया।

भूमिकाः सक्षमकताओं को सशक्त बनाना

रेहड़ी-पटरी विक्रेता, किसी भी शहर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। रेहड़ी-पटरी स्व-रोजगार का एक ऐसा स्वरूप है जो शहरी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह आबादी के सभी वर्गों को उनके घर पर ही वस्तुओं और सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को जिन प्रमुख चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है उनमें हैं - मान्यता का अभाव, औपचारिक ऋण तक उनकी सीमित पहुँच, शिक्षा एवं कुशलता के स्तर में कमी, निर्धारित वेंडिंग क्षेत्रों की कमी तथा उभरते बाजार अवसरों तक इनकी सीमित पहुँच शामिल हैं। रेहड़ी-पटरी विक्रेता असंगठित क्षेत्र के स्व-रोजगार में संलग्न होते हैं जिससे इन विक्रेताओं और उनके परिवारों का सामाजिक सुरक्षा से लेकर जन कल्याण तथा सरकारी सहायता की योजनाओं से जुड़ाव सीमित रहता है। परिणामस्वरूप, कठिन परिस्थितियों अथवा आकस्मिक आवश्यकताओं के समय उनकी स्थिति और चिंतनीय हो जाती है।

पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ जून 2020 में किया गया जिसका उद्देश्य महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय संकटों से उबरने तथा प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने में रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की सहायता करना था। हालांकि जब से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया, इसने न केवल रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को वित्तीय सहायता दी बल्कि इसने अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को औपचारिक पहचान एवं सम्मान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया।

27 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की ऋण अवधि को 31.12.2024 से आगे बढ़ाने तथा योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के बाद योजना की ऋण अवधि 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के लिए कुल परिव्यय ₹7,332 करोड़ है। पुनर्गठित योजना के अंतर्गत 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं।

ऋण वितरण एवं कल्याणकारी संबद्धताएँ

पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहले एवं दूसरे चरण के ऋण की राशि में वृद्धि, दूसरे चरण के ऋण की समय पर अदायगी करने वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना, तथा खुदरा एवं थोक लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान पर कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। योजना का विस्तार चरणबद्ध ढंग से सांविधिक कस्बों से आगे जनगणना नगरों, अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि तक किया जा रहा है।

संशोधित ऋण संरचना के अंतर्गत पहले चरण का ऋण ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000, दूसरे चरण का ऋण ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 जबकि तीसरे चरण में ऋण की राशि को बढ़ाकर ₹50,000 किया गया है।

यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को अचानक सामने आने वाली व्यावसाय से जुड़ी अथवा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल ऋण सुविधा प्रदान करेगा।

इससे आगे डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने हेतु रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए निम्नलिखित कैशबैक के प्रावधान किए गए हैं—

नियमित बिक्री पर अधिकतम ₹1,200 तक का कैशबैक (प्रति माह अधिकतम ₹100),

₹2,000 या उससे अधिक की थोक खरीद पर अधिकतम ₹400 तक का कैशबैक (प्रति लेन-देन ₹20, प्रति तिमाही अधिकतम ₹100)।

इस योजना को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आजीविका के अवसर को सशक्त करने, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए, सार्वजनिक प्रशासन में नवाचार (केंद्रीय स्तर), के लिए वर्ष 2023 का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार तथा डिजिटल परिवर्तन हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।

राहत से विकास की ओरः पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना

वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान छोटे ऋण सहायता के रूप में प्रारंभ की गई यह योजना, पुनर्गठन के पश्चात रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के समग्र विकास की परिकल्पना प्रस्तुत करती है। यह योजना व्यवसाय विस्तार के लिए विश्वसनीय वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ सतत विकास के अवसर भी प्रदान करती है।

पीलीभीतः भाजपा विधायक विवेक वर्मा की सौगात–देवहा नदी पर भौरूआ में बनेगा पुल, बीसलपुर-बरेली दूरी 10 किमी कम होगी

बीसलपुर। भाजपा विधायक विवेक कुमार वर्मा ने क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। देवहा नदी पर भौरूआ के पास ₹3169.49 लाख की लागत से दीर्घ सेतु का निर्माण होगा, जिससे बीसलपुर से बरेली की दूरी 10 किमी कम हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने कार्य स्वीकृत कर दिया है, पहली किश्त की धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होगा।

विधायक विवेक वर्मा ने बताया कि यह जन अपेक्षाओं व क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने का परिणाम है। उन्होंने कहा, "बेहतर सेतु ही तीव्र, समावेशी व संतुलित विकास की नींव हैं। हम अवसंरचनात्मक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" इससे स्थानीय आवागमन आसान होगा, किसानों व व्यापारियों को लाभ मिलेगा।

बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में यह पुल विकास की नई कड़ी साबित होगा। (विकास का पुल!)